VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)/GENERAL STUDIES (Paper-II) (2423)

निर्धारित समय: तीन घंटे | अधिकतम अंक: 250

*Time Allowed: **Three Hours*** | *Maximum Marks: 250*

सामान्य अनुदेश

इस प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका में 55+1 पृष्ठ हैं। प्रश्न-पत्र, क्यू.सी.ए. पुस्तिका के अंत में संलग्न है, जो अलग (वियोज्य) किया जा सकता है और उम्मीदवार परीक्षा के उपरांत अपने साथ ले जा सकते हैं।

रफ कार्य के लिए, इस पुस्तिका के अंत में खाली पृष्ठ दिया गया है।

पुस्तिका प्राप्त होने पर, कृपया यह जांच कर लें कि इस क्यू.सी.ए. पुस्तिका में कोई कमी न हो, फटा हुआ पृष्ठ न हो अथवा कोई पृष्ठ गायब न हो इत्यादि। यदि ऐसा हो, तो इसके बदले नई क्यू.सी.ए. पुस्तिका प्राप्त कर लें।

General Instructions

This Question-Cum-Answer (QCA) Booklet contains 55+1 pages. Question Paper in detachable form is available at the end of the QCA Booklet which can be taken away by the candidate after examination.

For rough work, blank page has been provided at the end of this Booklet.

On receipt of the Booklet, please check that this QCA Booklet does not have any shortcomings, torn or missing pages etc. If, so, get it replaced with a fresh QCA Booklet.

(उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा/To be filled by the Candidate)

पंजीकरण सं./Registration No. : 473817

अभ्यर्थी का नाम/Name of Student : Sandeep kumar meena

माध्यम: हिंदी/अंग्रेजी
Medium: Hindi/English
Hindi

तारीख
Date
26/8/23

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)
GENERAL STUDIES (Paper II)

केंद्र
Centre
Delhi

निरीक्षक के हस्ताक्षर
Invigilator's Signature

VISIONIAS

	महत्वपूर्ण अनुदेश	Important Instructions
	उम्मीदवारों को नीचे उल्लिखित निर्देश सावधानी से पढ़ लेने चाहिए। किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों को मिलने वाले अंकों में कटौती, उम्मीदवारी रद्द या आयोग के परवर्ती परीक्षाओं के लिए वर्जित करने इत्यादि के रूप में दण्डित किया जा सकता है।	**Candidates should read the undermentioned instructions carefully. Violation of any of the following instructions may entail penalty in the form of deduction of marks, cancellation of candidature, debarment from further Examination of the Commission etc.**
1	(क) अपना पंजीकरण सं. एवं अन्य विवरण केवल प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) में उम्मीदवार के लिए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। (ख) इस पुस्तिका में अन्यत्र कहीं भी अपना नाम, पंजीकरण सं., मोबाइल नं., पता अथवा प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) संख्या न लिखें जिससे आपकी पहचान का खुलासा हो।	(a) Write your Registration Number and other details only in the space provided in the Question-Cum-Answer (QCA) Booklet for candidates. (b) Do not disclose your identity in any manner such as, by writing your Name, Registration number, Mobile number, Address, Question-Cum-Answer (QCA) Booklet No. etc. elsewhere in the Booklet
2	अपनी प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में कहीं भी प्रश्नों के वास्तविक उत्तर के अतिरिक्त कुछ न लिखें जैसे कि कोई कविता/दोहा, अभद्र या अपमानजनक अभिव्यक्ति इत्यादि और न ही कोई ऐसा चिन्ह/निशान बनाएं जिसका उत्तर से सम्बन्ध न हो।	Do not write in the QCA Booklet anything other than the actual answer such as couplet, obscene, abusive expression etc., nor put any sign/mark having no relevance to the answer.
3	परीक्षक को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रार्थना/ धमकी भरी बातें न लिखें।	Do not make any direct/indirect appeal/threat to the examiner.
4	उत्तर अस्पष्ट अथवा गंदी लिखावट में न लिखें। इस प्रकार के उत्तर का मूल्यांकन नहीं भी किया जा सकता है।	Do not write answers in bad/illegible handwriting. Such answers may not be evaluated.
5	उत्तर स्याही में ही लिखें। उत्तर लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग न करें, हालांकि आरेख, चित्र इत्यादि बनाने के लिए पेंसिल का उपयोग किया जा सकता है।	Write answers in ink only. Do not use pencil for writing the answers. However, pencil may be used for drawing diagrams, sketches, etc.
6	प्रवेश पत्र में उल्लेख किए गए माध्यम के अलावा अन्य किसी माध्यम में उत्तर न लिखें। अधिकृत और अनधिकृत की मिली जुली भाषा का भी उपयोग न करें।	Do not write answers in medium other than the authorized medium in the Admission Certificate. Do not use mixed language either i.e. authorize and unauthorized media together for writing answers.
7	प्रश्नों के उत्तर ठीक उसके नीचे दिए गए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर लिखे गए उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।	Write answer at the specific space (right below the question) only. Answers written elsewhere at unspecified places in the booklet shall not be evaluated.
8	यदि आप अपने किसी उत्तर को रद्द करना चाहते हैं तो उसे पेन से काट दें तथा उस पर "रद्द" लिख दें, अन्यथा उसका मूल्यांकन किया जा सकता है।	If you wish to cancel any work, draw your pen through it and write "Cancelled" across it, otherwise it may be valued.

VISION IAS

कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use	कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use
परीक्षक के हस्ताक्षर Signature of Examiner(s)	

प्राप्तांक के विवरण (परीक्षक द्वारा भरा जाए)/ Marks Details (To be filled by the Examiner(s))

प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks		प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks	
1			11		
2			12		
3			13		
4			14		
5			15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10			20		
उप-योग (A) Subtotal (A)			उप-योग (B) Subtotal (B)		
सकल योग (A+B) / GRAND TOTAL (A+B)					

VISIONIAS

VISIONIAS

INSPIRING INNOVATION

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)/GENERAL STUDIES (Paper-II) (2423)

निर्धारित समय: **तीन** घंटे Time Allowed: **Three** Hours	अधिकतम अंक: **250** Maximum Marks: **250**

प्रश्न-पत्र संबंधी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

*कुल **बीस** प्रश्न दिए गए हैं जो **हिंदी** और **अंग्रेजी** दोनों में छपे हैं।*

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए।

प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखिए।

प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ भाग को पूर्णतः काट दीजिए।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

All questions are compulsory.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Answers to Questions No. 1 to 10 should be in 150 words, whereas answers to Questions No. 11 to 20 should be in 250 words.

Keep the word limit indicated in the questions in mind.

Any page or portion of the page left blank in the Questions-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS

1. उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से, चर्चा कीजिए कि पर्यावरणीय दबाव समूह भारत में पर्यावरण नीतियों के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी और अनुक्रियाशीलता को कैसे बढ़ाते हैं। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
With suitable examples, discuss how environmental pressure groups enhance public participation and responsiveness with regard to environmental policies in India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में, नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

दबाव समूह से तात्पर्य है कि ऐसे समूह जो दबाव, आंदोलन के माध्यम से नीति निर्माण को प्रभावित करे। पर्यावरण के क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। उदा. जल संरक्षण के लिए राजेन्द्र सिंह का NGO तरुण भारत संघ।

पर्यावरणीय दबाव समूह भारत में पर्यावरण नीतियों के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी और अनुक्रियाशीलता :-

(1) पर्यावरणीय समूह पर्यावरण के मूल्यांकन के लिए दबाव बनाते हैं।
उदा. नदी जोड़ो परियोजना का विरोध।

(2) जल संरक्षण के लिए कैच द रेन कार्यक्रम को प्रारंभ करना।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(3) पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार पर दबाव बनाना।
उदा. खेत में अवशिष्टों के जलाने पर रोक।

(4) नीति निर्माण में अनुक्रियाशीलता को बढ़ावा देना।

(5) नियमों के निर्माण
- पर्यावरण संरक्षण अधि., 1986
- जल संरक्षण अधि., 1980,

समग्रतः नीति निदेशक तत्व एवं मूल कर्तव्य भी पर्यावरण संरक्षण के लिए बढ़ावा देती है। दबाव समूह सरकार की नीतियों, निर्माण एवं क्रियान्वयन को अनुक्रियाशील बनाते हैं।

2. हाल ही में, उच्चतम न्यायालय द्वारा सेक्स वर्क को एक 'पेशे' के रूप में स्वीकार किया जाना, भारत में सेक्स वर्कर्स के लिए बुनियादी अधिकार और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है। परीक्षण कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

The recent acknowledgment of sex work as a 'profession' by the Supreme Court is merely the first step in ensuring basic rights and equality for sex workers in India. Examine. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उच्चतम न्यायालय ने सेक्स वर्क को पेशे के रूप में स्वीकार करके एक सुधारात्मक पहल की है जिससे इस क्षेत्र में मानव अधिकार एवं मूलभूत जरूरतों को पूरा हो सके।

भारत में सेक्स वर्कस के लिए बुनियादी अधिकार और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में पहल :-

(1) सेक्स वर्कस की मानव तस्करी को रोकने में मदद।

(2) पुलिस एवं अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दुरुपयोग से सुरक्षा।

(3) आवश्यक सुरक्षा इंतजामों तक पहुँच बढ़ सकेगी।

(4) ग्राहकों के अनावश्यक शोषण से मुक्ति।

कुछ चुनौतियाँ :-

→ सेक्स वर्कर्स की संख्या बढ़ाने हेतु मानव तस्करी।
→ कानून प्रवर्तन में अनावश्यक दिक्कतें।
→ पहचान का ~~इश्यू~~ मुद्दा।

अत: सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में स्वीकार करके वंचित, सुभेद्य महिलाओं को गरिमामय, बेहतर जीवन प्रदान कर सकेंगे। इससे वे मूलभूत अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अपनी अव संतानों की बेहतर जीविका सुनिश्चित हो सकेगी।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

3. भारत में नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने और कानूनी जागरूकता फैलाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSAs) द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Discuss the role played by District Legal Services Authorities (DLSAs) in providing free legal aid and disseminating legal awareness in India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

DPSP के क्रियान्वयन एवं न्याय तक बेहतर पहुँच को सुनिश्चित करने राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन किया है।

भारत में नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने और कानूनी जागरूकता फैलाने में DLSAs की भूमिका :-

(1) DLSAs समाज के वंचित, गरीब एवं सुभेद्य वर्गों की न्याय तक पहुँच को व्यापक बनाते हैं।

(2) जिला न्यायलय में नि: शुल्क विधिक सहायता प्रदान करना।

(3) न्यायिक जागरूकता जिसमें महिलाओं के अधिकार भी शामिल है।

(4) न्याय में लोगों के विश्वास में वृद्धि करना।

(5) न्याय की प्रक्रिया एवं न्याय प्राप्त करने में लोगों की सहायता करना।

(6) समाज में कानून के शासन के महत्व को बताना।

समग्रत: अधीनस्थ एवं जिला न्यायालयों में 3.5करोड वाद लंबित है जिनके निस्तारण DLSAs की भूमिका महत्वपूर्ण एवं प्रभावकारी हो सकती है। इसे और प्रभावी बनाने के लिए अधिक वकीलों को शामिल करें।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

4. "कुछ लोगों के हाथों में शक्ति के संकेंद्रण के कारण, कॉलेजियम प्रणाली अपनी ही सफलता का शिकार हो गई है, जिससे इसकी वैधता पर सवाल उठने लगे हैं।" टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

"The collegium system has become a victim of its own success, with the concentration of power in the hands of a few, leading to questions about its legitimacy." Comment. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

कोलेजियम प्रणाली तीन 3rd जज वाद में मुख्य न्यायधीश के साथ चार न्यायधीशों की राय को सम्मीलित करती है यह उच्च एवं उच्चतम न्यायलय में न्यायधीशों की नियुक्ति करती है।

कुछ लोगों के हाथों में शक्ति के संकेंद्रण के कारण, कोलेजियम प्रणाली अपनी ही सफलता की शिकार हो गई क्योंकि:-

(1) कोलेजियम प्रणाली पर शक्ति के पृथक्करण का उल्लंघन का आरोप है।

(2) कोलेजियम प्रणाली के बाद भी उच्च न्यायलयों में रिक्तियों को न भरा जाना।

(3) न्यायिक प्रणाली द्वारा पारदर्शिता

के उच्च मानदंडों को न अपनाना।

(4) पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता जैसे मूल्यों का बेहतर निष्पादन न किया जाना।

वैधता पर सवाल :-

→ NJAC को रद्द करने के बाद बेहतर व्यवस्था को न अपनाना

→ न्यायिक प्रणाली अंकल जज सिंड्रोम का सामना करना

→ भारत न्यायिक अति सक्रियता का सामना करना।

निष्कर्ष : न्याय प्रणाली को पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, समावेशिता जैसे मूल्यों को कॉलेजियम में शामिल करें और जनता को सभी तथ्यात्मक जानकारी देकर विश्वसनीयता बढ़ानी चाहिए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

5. "सिविल सेवा सुधारों को वर्तमान दौर की चुनौतियों से निपटने के लिए भर्ती और मानकीकृत प्रशिक्षण से आगे बढ़ाया जाना अनिवार्य है।" विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
"Civil services reforms must go beyond recruitment and standardised training to cope with the present day challenges." Analyse. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

" सिविल सेवा नैतिक कार्य एवं सिविल सेवक नैतिक अभिकर्ता है।"
आडवे टीड

सिविल सेवा सुधारों को वर्तमान दौर की चुनौतियों से निपटने के लिए भर्ती और मानकीकृत से आगे बढ़ाया जाना अनिवार्य क्योंकि :-

(1) वर्तमान समय में नई चुनौतियाँ हैं जिससे सिविल सेवकों को निपटना है। उदा. साईबर सुरक्षा।

(2) मिड टर्म प्रशिक्षण कार्यक्रम को शामिल करो।
— 2nd ARC की 10th रिपोर्ट।

(3) मिशन कर्मयोगी में मिड टर्म

प्रशिक्षण।

(4) 360° निष्पादन के साथ ही मूल्यांकन पद्धति को बढ़ावा दें।

(5) मूल्यांकन के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसे निर्णयों को शामिल करें।

(6) सिविल सेवकों की लेटरल एंट्री प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकती है।

स्पष्टतः सिविल सेवा सुधारों को भर्ती एवं मानकीकृत प्रशिक्षण से आगे बढ़ाकर तकनीकी दक्ष, जनोन्मुख, दक्षता आधारित एवं निष्पादन को बेहतर करने पर बल देना होगा।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

6. सामाजिक प्रभाव बॉण्ड्स जैसे परिणाम-आधारित वित्त मॉडल में वास्तविक रूप से परिवर्तन लाने और बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता विद्यमान है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Outcome-based finance models such as social impact bonds have the potential to truly catalyse change and deliver socio-economic impact at scale. Discuss. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सामाजिक प्रभाव बांड्स को हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बढ़ावा देने हेतु प्रयास किये है। इस हेतु SEBI ने सोशल स्टाक एक्सचेंज की स्थापना भी की है।

SIBs जैसे परिणाम आधारित वित्त मॉडल में वास्तविक रूप से परिवर्तन लाने और बड़े पैमाने पर सामाजिक - आर्थिक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता :

① सामाजिक प्रभाव बांड्स समाज में परिवर्तन को लागू करने वाली सामाजिक प्रभाव योजनाओं के लिए
उदा. वृद्ध सशक्तिकरण

② तकनीक रूप से समाज के सुभेद्य एवं वंचित वर्गों के सशक्तिकरण।
उदा. निर्भया फंड

3. नगर निगम एवं स्थापत्त संस्थाओं के लिए धन जुटाना।

ex: अहमदाबाद नगर निगम

4. सामाजिक सुधार संगठनों की वित्त जरूरतों को पूरा करना।

समग्रत: सामाजिक प्रभाव बाण्ड्स वित्त की जरूरतों को पूरा करते हुए सामाजिक क्रांति, सामाजिक सशक्तीकरण एवं वंचित व सुभेद्य वर्गों के अधिकारों में उल्लेखनीय भूमिका निभा सकती है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

7. प्रत्येक वर्ष ग्रेजुएट होने वाली और कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने वाली महिलाओं की संख्या के मध्य का व्यापक अंतराल एक गंभीर समस्या है जिसे हल किए जाने की आवश्यकता है। भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

The wide gap between the number of females graduating every year and those entering the workspace is an issue of paramount importance that needs to be addressed. Discuss in the context of India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत में LFPR की दर 32.8% है जबकि ग्रेजुएट होने वाली महिलाओं की संख्या अधिक है

* मध्य का व्यापक अंतराल एक गंभीर समस्या कैसे :-

→ भारत की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की संख्या को बढ़ाना – आर्थिक सशक्तीकरण।

→ आर्थिक सशक्त महिला अपने बच्चों को भी बेहतर शिक्षा देगी।

→ आय के साधन पोषण पर खर्च

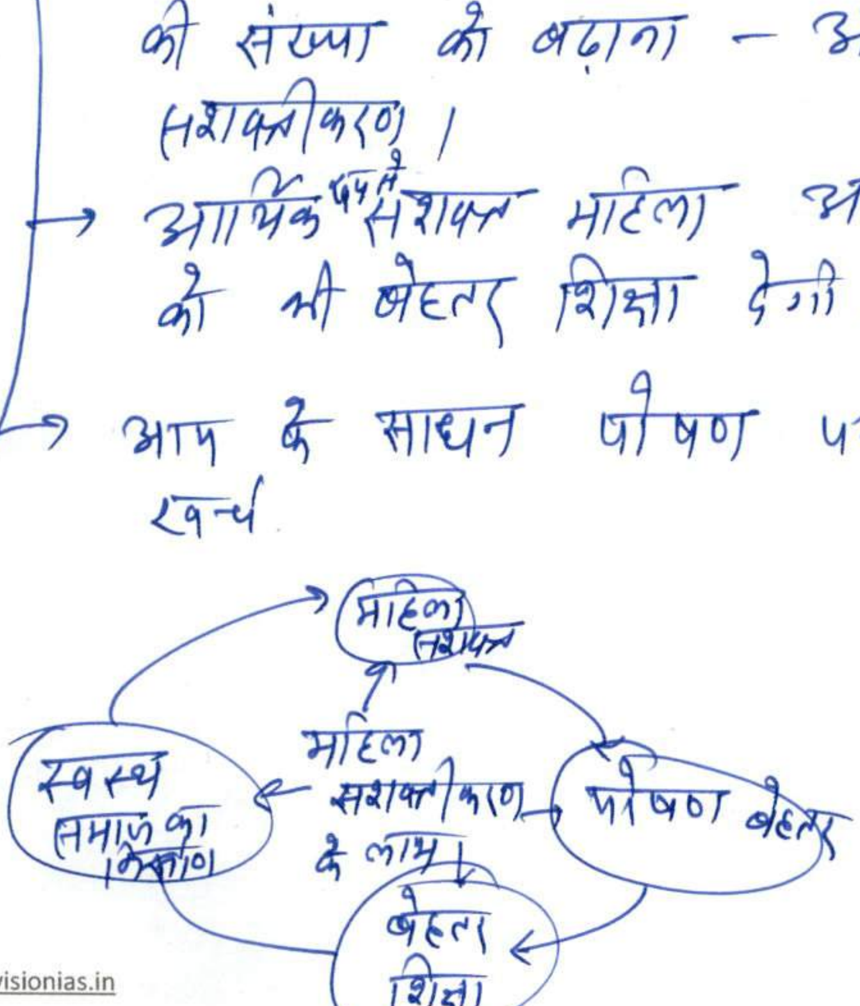

मैजुरल एवं कार्यक्षेत्र को हल किये जाने की आवश्यकता :-

① भारत की GDP को 14% बढ़ा सकते हैं यदि हम LFPR को बराबर भागीदारी सुनिश्चित करें।

② समावेशी विकास

③ महिला सशक्तीकरण < आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक

④ सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति (SDG-5)

समग्रत: महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना होगा। महिलाओं को लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करके ही समावेशी समाज एवं सशक्त भारत का निर्माण हो सकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

8. भारत में सामाजिक-आर्थिक नियोजन के लिए एक अद्यतित और कार्यात्मक नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) अनिवार्य है। देश में CRS प्रणाली में सुधार हेतु केंद्र सरकार के हालिया कदम के आलोक में चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

An up to date and functional Civil Registration System (CRS) is essential to the socio-economic planning in India. Discuss in the light of the recent move of the Central government in revamping the CRS system in the country. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

CRS के माध्यम से नागरिकों का डेटा का बेहतर जानकारी एवं नीति निर्माण हेतु उपयोगी बना सकते हैं।

~~सामाजिक~~
CRS प्रणाली में सुधार हेतु केंद्र सरकार के हालिया कदम :-

1. प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के समय ही पंजीकरण करना। इसमें माता-पिता के आधार डाटा का उपयोग।

2. मृत्यु का पंजीकरण करना।

3. प्रत्येक बच्चों की टीकाकरण एवं शिक्षा के रिकॉर्ड को रखना।

CRS सामाजिक - आर्थिक नियोजन के लिए भूमिका :-

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(1) नियोजन बेहतर
(2) मांग आधारित नियोजन
(3) DBT का बेहतर क्रियान्वयन
(4) बच्चों के पोषण की monitoring.

समग्रतः CRS के माध्यम से कुपोषण, शिक्षा एवं DBT का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। CRS एक राष्ट्र व्यापी प्रवासियों का डेटा का प्रबंधन को बेहतर तरीके से कर सकते हैं।

9. यदि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के साथ समायोजित होना है तो इसमें सुधार के प्रमुख क्षेत्र कौन-से होंगे? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

What are the key areas of reform if the International Monetary Fund (IMF) has to align with the current economic realities? (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

IMF ब्रिटेनवुड समझौता के तहत वैश्विक विनमय प्रणाली को प्रबंधित करने के लिए 1944 में निर्मित संगठन है।

IMF को वर्तमान आर्थिक आवश्यकताओं के साथ समायोजित होने हेतु सुधार :-

① IMF को चीन एवं भारत जैसे देशों को अर्थव्यवस्था के आकार में प्रतिनिधित्व देना।

② विनमय प्रणाली में डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं को स्थान देना।

③ कोटा सुधारों को लागू करना।

④ IMF को संरक्षणवादी प्रवृत्तियों से बचाना होगा।

⑤ ~~विश्व~~ IMF वर्तमान विश्व का प्रतिनिधित्व करे। जिसके लिए

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अफ्रीका एवं एशिया का प्रतिनिधित्व बढ़ाना होगा।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

क्या किया जाना चाहिए

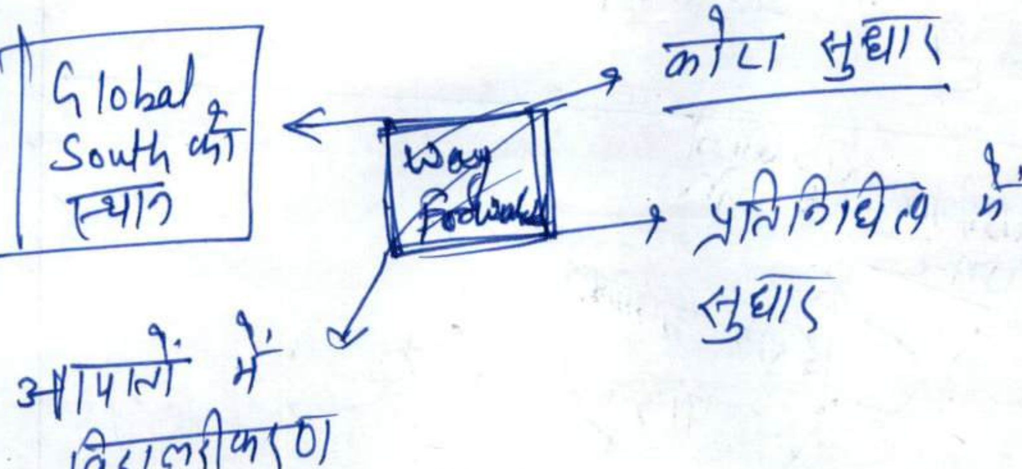

समग्रतः हम कह सकते हैं कि G-20 देशों को अपनी अर्थव्यवस्था के आकार में वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO जैसे संगठनों में नये कोटा एवं प्रतिनिधित्व प्रदान करें।

10. हाल के वर्षों में, पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंध भू-राजनीति के दायरे से आगे निकलकर भू-अर्थशास्त्र के आयाम तक पहुंच गए हैं। विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

In recent years, India's relationship with West Asia has evolved from the confines of geopolitics to expanse of geoeconomics. Discuss. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

पश्चिमी एशिया भारत के साथ व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा एवं सामरिक संबंधों का विस्तार देखने को मिल रहा है

पश्चिमी एशिया में भू-अर्थशास्त्र के आयाम :-

(1) UAE भारत की 22% तेल आयात

को पूरा कर रहा है।

2. UAE ने रिलायंस के साथ मिलकर रत्नागिरी रिफाइनरी project में FDI का निवेश कर रहा।

3. ईरान भारत की आयात जरूरतें पूरी कर रहा है।

4. पश्चिमी एशिया में भारतीय प्रवासी सर्वाधिक रहते हैं।

5. INSTC कॉरिडोर, TAPI project

समग्रतः पश्चिमी एशिया वर्तमान में भू-राजनीति के स्थान से आगे बढ़कर भारत के लिए निवेश, रिमिटेन्स प्रवासी भारतीय जैसे मुद्दों पर सहयोग कर रहा है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

11. हितधारकों को नवाचार और प्रभावशीलता में वृद्धि हेतु प्रेरित करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की भूमिका महत्वपूर्ण है। टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The role of the Competition Commission of India (CCI) is significant in furthering healthy competitiveness aimed at inspiring stakeholders to innovate and augment effectiveness. Comment. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाल ही में प्रतिस्पर्धात्मक अधिनियम में परिवर्तन किये गये हैं। इससे अधिनियम को अधिक प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलेगी।

हितधारकों को नवाचार और प्रभावशीलता में वृद्धि हेतु प्रेरित करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देने में CCI की भूमिका :-

(1) CCI सभी कंपनियों को नवाचार हेतु समान प्लेटफोर्म का निर्माण करता है।

(2) CCI सभी हितधारकों के प्राकृतिक न्याय की अवधारणा की अनुपालना सुनिश्चित करता है।

(3) CCI के माध्यम से पेटेंट अधिकारों

को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

(4) कंपनी अधिनियम के खिलाफ सुनवाई।

(5) व्यापार समझौते एवं व्यापार माहौल को बनाये रखने हेतु बेहतर क्रियान्वयन।

चुनौतियाँ :-

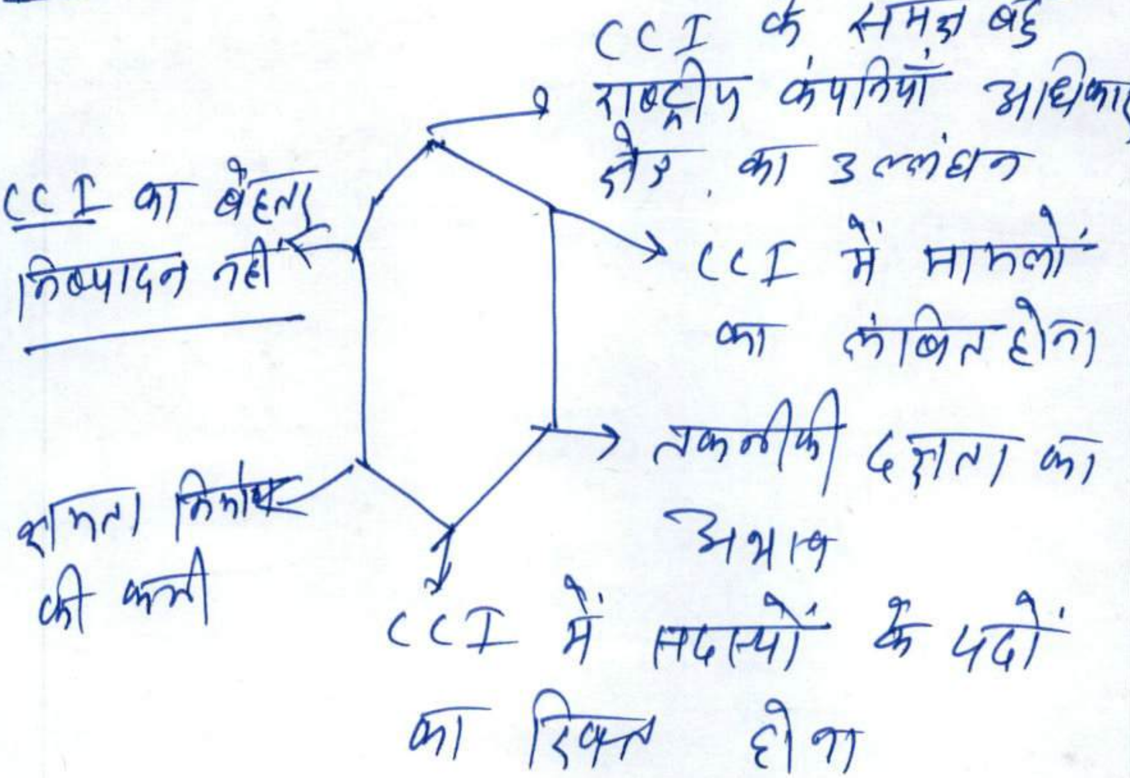

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

स्पष्टतः CCI ने 2003 के बाद से व्यापार के संरक्षण के लिए बेहतर रूप से कार्य किया है लेकिन भारत की ease of doing business रैंकिंग में सुधार करने हेतु व्यापार, व्यापार समझौते की प्रभावशीलता में बेहतर निष्पादन की आवश्यकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

12. "पेड़ न्यूज का खतरा अक्सर चुनावों के दौरान अपना भयावह रूप दिखाता है।" भारत में पेड न्यूज को एक चुनावी अपराध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
"The menace of paid news often rears its ugly head during elections." Discuss the need for making paid news an electoral offence in India. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

पेड न्यूज से तात्पर्य है कि ~~साम~~ विज्ञापन को धन लेकर समाचार के रूप में प्रेषित करना। जिससे विज्ञापन का प्रभाव अधिक होता है।

पेड न्यूज का खतरा अक्सर चुनावों के दौरान अपना भयावह रूप दिखाता है:-

① आदर्श आचार संहिता के क्रियान्वयन को प्रभावित करता है।

② चुनाव के परिणाम को अवांछित रूप से प्रभावित।

③ समाचार पत्रों के साथ सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसकी भयावहता को अधिक व्यापक बना देती है।

④ इस पर राजनीतिक दलों के खर्च

अधिक होता है।

(5) जनता के मनोबल एवं कुंठा की भावना देखने को मिलती है।

(6) पेड न्यूज ने समाज में नेताओं, दलों की भूमिका को प्रभावित किया है।

पेड न्यूज को चुनावी अपराध बनाने की आवश्यकता:

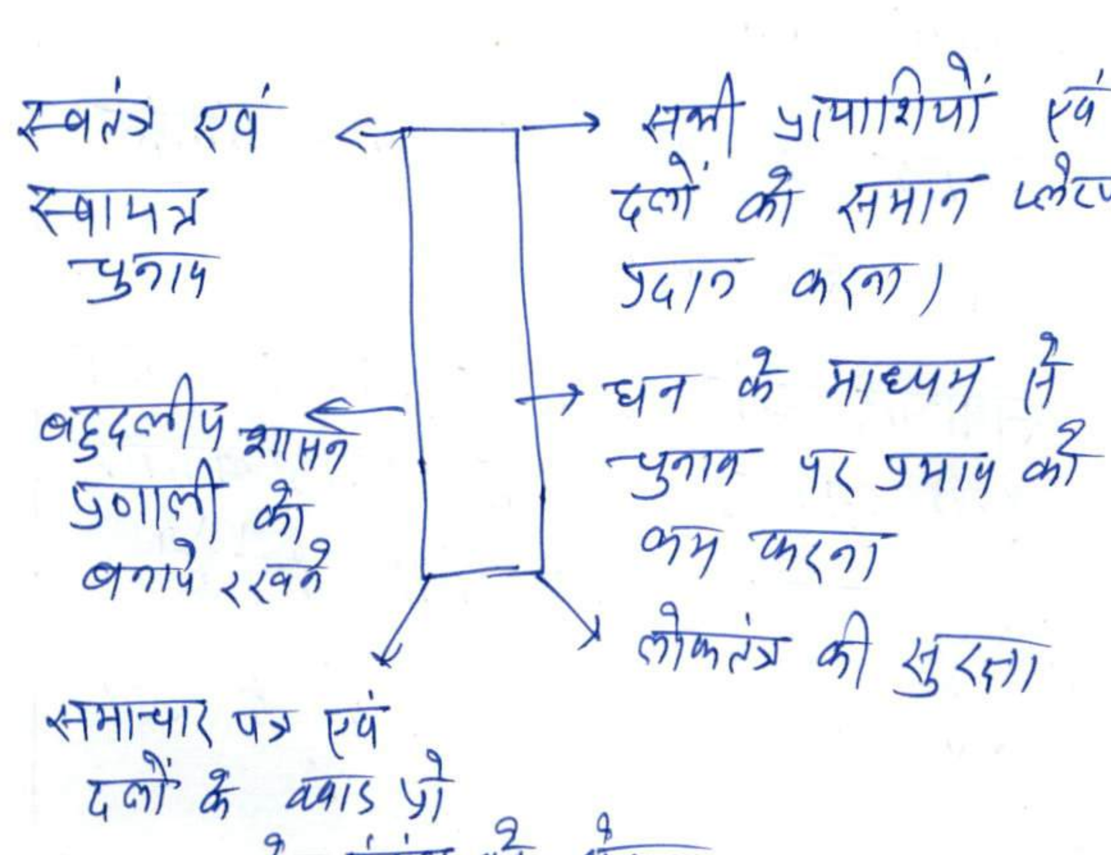

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

चुनाव आयोग की पहल :-

1. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का बेहतर
2. आदर्श आचार संहिता के माध्यम से सबको बराबर अवसर प्रदान करना।
3. चुनाव के 48 घंटों से पहले चुनाव प्रचार पर रोक।

निष्कर्ष: पेड न्यूज पर प्रभावी रोक लगाकर ही स्वतंत्र, सापन्न एवं समान रूप से सभी दलों एवं प्रत्याशियों को अवसर उपलब्ध करवाये जा सकते हैं।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

13. भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में, न्यायालयों द्वारा उद्धृत 'अनिवार्यता के सिद्धांत' पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Discuss the 'Doctrine of Essentiality' referred to by the courts in the context of religious practices in India. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

अनिवार्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय ने धर्म की अनिवार्य प्रथाओं एवं रीतियों के पालन हेतु किया है। उदा. सिख धर्म में पगड़ी बांधना

न्यायलयों द्वारा उद्धृत अनिवार्यता का सिद्धांत :-

① इससे धार्मिक प्रथाओं का सार्वजनिक प्रदर्शन को प्रतिबंधित करने में मदद मिल सकती है।
जैसे जुलूस के दौरान हथियारों के प्रदर्शन पर रोक।

② इससे धार्मिक समन्वय एवं सौहार्द्र में मदद मिलती है।

③ हाल ही में हिजाब विवाद में भी सर्वोच्च न्यायलय ने अनिवार्यता

के सिद्धांत की व्याख्या की।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

चुनौतियाँ :-

① प्रथाओं की अनिवार्यता के सिद्धांत का परीक्षण न्यायधीशों के स्थान पर धर्म गुरु बेहतर कर सकते हैं।

② न्यायधीशों के पास धार्मिक विशेषज्ञता का अभाव।

③ धर्म को मानने का अधिकार व्यक्तिगत मामला है (अनुच्छेद - 25)

④ **क्या किया जाना चाहिए :-**

① प्रत्येक धर्म में मूल मूल्य पर ध्यान दें। जैसे दया, करुणा।

② दूसरे धर्म की वो प्रथा जो अनावश्यक

www.visionias.in

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए Candidates must not write on this margin

रूप से किसी को नुकसान पहुँचाये उन पर रोक हो।

समग्रतः अनिवार्यता का सिद्धांत सार्वजनिक जीवन, धर्म एवं अन्य धर्मों के साथ संबंधों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।

14. प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सरकार के आकार को सीमित करने की तत्काल आवश्यकता है। क्या आप सहमत हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

As per the recently released report of the Economic Advisory Council to the Prime Minister (EAC-PM), there is an urgent need to limit the size of the government in India. Do you agree? (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत सरकार के राजस्व खर्च 35 लाख करोड़ है। इनका बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा पेंशन, वेतन जैसे सरकारी खर्चों पर खर्च होता है।

EAC-PM की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सरकार के आकार को सीमित करने की तत्काल आवश्यकता :

1. सरकार के राजस्व खर्च को कम करके पूंजीगत खर्च बढ़ा सकते हैं।
2. पूंजीगत खर्च का प्रभाव बहु आयामी एवं व्यापक होता है।
3. पूंजीगत खर्च के माध्यम से आधारभूत संरचना में निवेश से लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने में मदद।
4. लॉजिस्टिक लागत कम करके निवेश को बढ़ावा।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(5) प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

(6) तकनीक के माध्यम से सरकार के कार्यों को कम आकार से भी विस्तारण किया जाना चाहिए।

(7) शक्तियों का स्थानीय स्तर पर प्रायोजन

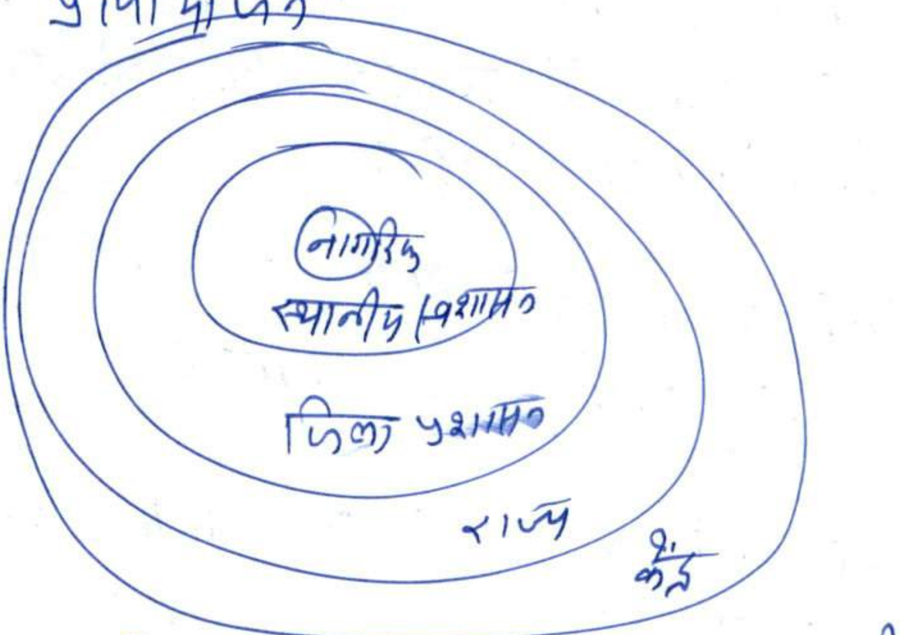

(8) शक्तियाँ केंद्र से परिधि की ओर गमन करें। प्रशासन की लागत व आकार कम।

चुनौतियाँ :-

- जन कल्याण राज्य का उद्देश्य
- **issues**
- 140 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा जैसे मुद्दे ex: पुलिस, सेना पर खर्च
- विविधता का समावेश ex: मंत्रीमंडल
- कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च।

अत: हमें प्रशासन के आकार को कम करके ही जनता के कल्याण के भाव को सुनिश्चित करना होगा। पूंजीगत खर्च को बढ़ाकर, राजस्व खर्च कम करके, निजी क्षेत्र की ~~सीमित~~ भागीदारी बढ़ाकर बेहतर वित्तीय प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा सकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

15. इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस (IoE) योजना की कल्पना भारत में उच्चतर शिक्षा के 'विश्व स्तरीय' केंद्र विकसित करने के लिए की गई थी, लेकिन छह साल बाद भी, यह अभी तक गेम चेंजर नहीं बन पाई है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
The Institutions of Eminence (IoE) scheme was conceived to develop 'world-class' centres of higher education in India but six years later, it is yet to become the game changer it was intended to be. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस योजना भारत के विश्वविद्यालयों को आर्थिक अनुदान एवं अन्य सुविधाएँ देकर विश्व के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में सम्मिलित करना है।

IoE की असफलता के कारण :-

1. संस्थानों को पाठ्यक्रम के निर्धारण जैसे विभिन्न आयामों में पर्याप्त स्वायत्तता का न देना।
2. पर्याप्त वित्तीय सहायता का न मिल पाना।
3. भारत में शोध पर कम खर्च किया जाता है

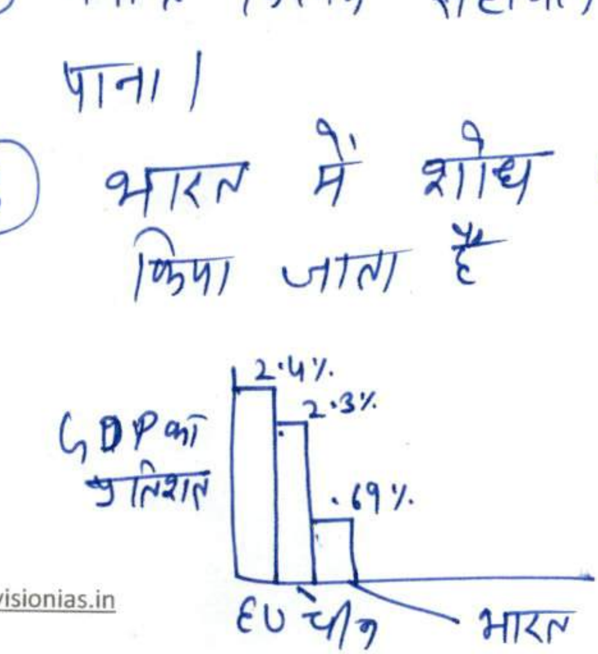

(4) IOE के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हस्तक्षेप।

(5) विश्व के विश्वविद्यालयों के साथ बेहतर समन्वय का अभाव।

(6) निजी क्षेत्र के निवेश की कमी

(7) नियामकीय एवं नियमों का आधिक्य होना

उदा. - UGC, NMC

क्या किया जाना चाहिए :

(1) शोध को बढ़ावा
(2) विश्व की सर्वोत्तम प्रणालियों से सीखना चाहिए।

(3) भारत को विश्व में प्रचार-प्रसार पर ध्यान - Branding

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(4) IOE को अधिक स्वायत्तता प्रदान करो।

(5) निजी क्षेत्र को स्वायत्तता एवं आर्थिक सहायता देनी चाहिए।

(6) विश्व की बेस्ट युनिवर्सिटीज को भारत में ब्रांच खोलने की अनुमति – spillover प्रभाव होगा।

(7) फैकल्टी को बेहतर प्रशिक्षण।

समग्रतः : IOE की स्वायत्तता, वित्तीय, बेहतर समन्वय जैसी सुविधा प्रदान करके इस योजना का बेहतर क्रियान्वयन करने में सहायक होगा। यह भारत से विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या को भी कम करेगा।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

16. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) नवोन्मेषी और सुविधाजनक सार्वजनिक सेवाओं की अनुमति देता है, समावेशन या पहुंच संबंधी बाधाओं को दूर करने में मदद करता है तथा रियल-टाइम डेटा की मदद से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाता है। उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Digital Public Infrastructure (DPI) allows for innovative and convenient public services, help overcome inclusion or accessibility barriers, and increase transparency and accountability with real-time data. Discuss with examples. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

2nd ARC की 11वीं रिपोर्ट ई-गवर्नेन्स को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करती है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नवोन्मेषी और सार्वजनिक सेवाओं की अनुमति देता है:-

① DPI के नवोन्मेष के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सेवाओं की शुरुआत हुई है।
- ई-मित्र, आधार, JAM ट्रिनिटी

② सार्वजनिक सेवाओं में DPI को प्रोत्साहन दिया है।
ex: फेसलेस एसेसमेंट आयकर विभाग की पहल।

③ आयुष्मान भारत योजना में डिजिटल

~~को दूर~~ हिस्ट्री को रिकॉर्ड करता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

DPI समावेशन एवं पहुँच संबंधी बाधा को दूर करने :-

1. गरीब एवं वंचितों की समान पहुँच सुनिश्चित करता है।
2. ई-प्लेटफोर्मों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य
   ex: ई-संजीवनी, स्वयं पोर्टल
3. सरकारी योजनाओं के लाभ को समावेशी बना दिया।

DPI रियल-टाइम डेटा की मदद से पारदर्शिता व जवाबदेहिता को बढ़ाता है :-

1. रियल टाइम डेटा के माध्यम से प्रशासन अनुक्रियाशील बना है।
   → नीति निर्माण में इंटरनेट के माध्यम से जनता की भागीदारी।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(2) RTI की रियल टाइम जानकारी देना
उदा - जन सूचना पोर्टल, राजस्थान

(3) सोशल मीडिया पर सरकार के अधिकारियों की जनता द्वारा जवाबदेही तय करना।

(4) ~~अच्छे~~ PDS के वाहनों को GPS के माध्यम से ट्रैक करना।

समग्रत: DPI ने नवोन्मेषी एवं सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में 360° परिवर्तन किया है यह परिवर्तन प्रशासन को जवाबदेही, अनुक्रियाशील पारदर्शी सुशासन से नैतिक शासन की ओर गतिमान है।

17. कानून के अलावा, भारत में 'सभी के लिए स्वास्थ्य के अधिकार' की पूर्ण प्राप्ति हेतु सामाजिक, वित्तीय और बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Besides legislation, the full realisation of the 'right to health for all' in India demands plugging of social, financial, and infrastructural gaps. Examine. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाल ही में राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य को अधिकार के रूप में कानूनी मान्यता वाला प्रथम राज्य बना है।

भारत में "सभी के लिए स्वास्थ्य के अधिकार की प्राप्ति हेतु सामाजिक, वित्तीय और बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने की आवश्यकता :-

सामाजिक

- स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच वंचित वर्गों तक पहुंचाना - ST, SC, महिला
- बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखना
- महिलाओं की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना
- महिलाओं की समुचित भागीदारी

वित्तीय :-

स्वास्थ्य बीमा का निम्न घनत्व

निजी स्वास्थ्य सुविधाओं का महँगी होना

→ राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार स्वास्थ्य पर GDP का 2.5% खर्च करना। वर्तमान में 1.5%

→ out of pocket व्यय
49% (2022)
60% (2018)

बुनियादी ढांचे की कमियां :-

→ भारत में एलोपैथिक डॉक्टर का अनुपात 1:1400 है।

→ ग्रामीण क्षेत्रों में कुल डॉक्टरों का 30% है।

→ बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में विषम अनुपात, बेडों की संख्या का कम।

→ राजस्थान में मेडिकल college की संख्या कम।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उपर्युक्त चुनौतियों के लिए सरकार के प्रयास :-

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए Candidates must not write on this margin

1. आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन
2. ई - संजीवनी
3. PM - जन औषधी - जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा।
4. व्यवहारगत बदलाव - योग, व्यायाम आदि को बढ़ावा देना।
5. मोटे अनाज आदि के माध्यम से पोषण पर बल।
6. PM - जननी सुरक्षा योजना

समग्रत: सार्वभौमिक स्वास्थ्य के कानूनी अधिकार को लागू करने से पहले हमें स्वास्थ्य क्षेत्र में GDP का 3% व्यय, बुनियादी ढांचे, पोषण, स्वच्छता जैसे मानकों के पालन पर ध्यान देना होगा।

18. विधायी समर्थन के बावजूद 'थर्ड जेंडर' को अभी तक भारतीय समाज में मान्यता नहीं मिली है। विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
The 'third gender' has not yet been engendered in the Indian society despite legislative nudge. Analyse. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत में ट्रांस जेंडर अधिनियम पारित कर दिया गया है। भारत में ट्रांस जेंडरों की संख्या कुल जनसंख्या का 2.5% है।

थर्ड जेंडर द्वारा सामना की जाने वाली समस्या :

1. शिक्षा के अधिकार से वंचित
2. पहचान के अधिकार से वंचित। हालांकि अधिनियम में स्वघोषणा का प्रावधान किया है।
3. परिवार के साथ सम्मानजनक रूप से मान्यता नहीं।
4. आजीविका के अधिकारों से वंचित।
5. विधायी प्रतिनिधित्व का न होना।

www.visionias.in

थर्ड जेंडर को मान्यता देने हेतु सरकारी प्रयास :-

1. थर्ड जेंडर के लिए अधिनियम पारित करना
2. स्वघोषणा जिसको जिला अधिकारी द्वारा मान्यता दिलवाना
3. स्वास्थ्य एवं शिक्षा के विशेष प्रावधान
4. सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय में एक बोर्ड का गठन।

क्या किया जाना चाहिए :-

1. थर्ड जेंडर के प्रति सामाजिक अभिवृत्ति में परिवर्तन।
2. किसी कमी के रूप में न देखकर उनके बेहतर सामाजीकरण का

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

प्रयास करना चाहिए।

(4) प्रशिक्षण संस्थानों में बेहतर सुविधा एवं बच्चों का sensitisation करना चाहिए।

समग्रत: थर्ड जेंडर एक जैनेटिक विसंगति है, इसे सामाजिक विसंगति न बनने दें। प्रत्येक व्यक्ति को गरिमामय जीवन के अधिकार प्रदान करना चाहिए। Art-21 की पहुँच का लाभ थर्ड जेंडर को भी मिलना चाहिए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

www.visionias.in

19. अन्य कारकों के अलावा, चीन और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंधों ने भारत के लिए शंघाई सहयोग संगठन (SCO) से अपनी अपेक्षाओं को पूरा करना कठिन बना दिया है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Among other factors, strained ties with China and Pakistan make it difficult for India to fulfill its expectations from the Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

शंघाई सहयोग संगठन मध्य एशियाई देशों का आतंक के विरोध में गठित संगठन है। इसे NATO का विरोधी संगठन माना जाता है।

इस संगठन में रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देश सदस्य है।

चीन और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंधों ने भारत के लिए SCO से अपनी अपेक्षाओं को पूरा करना कठिन :-

(1) SCO मध्य एशियाई देशों के लिए एक प्लेटफोर्म है लेकिन भारत इस संगठन में आतंक विरोधी मुहिम को बल नहीं मिला।

(2) भारत के किसी भी प्रस्ताव पर चीन एवं पाक की आपत्ति।

③ भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद नहीं मिल रही है।

④ ~~कोष~~ सेवा के निर्यात को भी बल नहीं।

⑤ तकनीक प्राप्ति में भी कोई समझौता नहीं

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

~~क्या~~ SCO का भारत के लिए महत्व :-

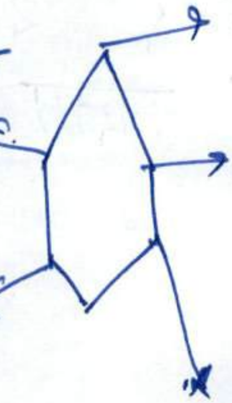

क्या किया जाना चाहिए :-

① SCO के मंच पर भारत अपनी बात को आसानी से रख सकता है

(2) इसके माध्यम से CCIT जैसे आतंक के मूल्यों पर एकजुटता का प्रयास।

(3) चीन एवं पाक के साथ बातचीत का माध्यम।

समग्रत: चीन एवं पाक के विरोध के बावजूद भारत अपनी जरूरतों के लिए SCO का बेहतर कूटनीतिक उपयोग करने में सक्षम हो सकता है

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

20. संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकी (iCET) पर हाल ही में संपन्न पहल, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनकी साझेदारी में लंबे समय से प्रतीक्षित परिवर्तन का वादा करती है। परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The recently concluded initiative on Critical and Emerging Technology (iCET) between the United States and India promises a long overdue transformation of their partnership in the field of technology. Examine. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत एवं USA वर्तमान में सामरिक, आर्थिक एवं राजनैतिक संबंधों का मजबूत स्तर पर पहुँच गया है। भारत का व्यापार USA के साथ आधिशेष में है।

USA और भारत के बीच iCET पर हाल ही में संपन्न पहल :-

① भारत एवं USA AI का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे।

② अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग
ex: चंद्रयान -3 में NASA का सहयोग।

③ क्वांटम प्रौद्योगिकी के उपयोग को ~~लिए~~ बेहतर बनाने में समझौता।

④ भारत को तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करके विनिर्माण क्षेत्र में

अग्रणी देश बनाना।

(5) न्यूक्लीयर तकनीक में सहयोग करके ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायता।

(6) भारत -चीन +1 की रणनीति को आगे बढ़ने के लिए USA का सहयोग।

(7) SCRI में भारत की भूमिका।

(8) सौर ऊर्जा - One Sun one grid one earth की पहल को बढ़ावा।

(9) समग्रत: AI, मशीन लर्निंग, क्वांटम, रोबोटिक्स, ड्रोन जैसी

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

आधुनिक तकनीक में USA भारत को सहयोग प्रदान करके विश्व में तकनीक क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। यह चीन को प्रतिसंतुलित करने की रणनीति भी है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

SPACE FOR ROUGH WORK